भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1244
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

ई-ग्रामस्वराज का कार्यान्वयन

1244. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः
श्री नबा चरणमाझीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामस्वराज के कार्यान्वयन और अपनाने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में ई-ग्रामस्वराज को पंचायतों के कामकाज में सुधार करने के लिए अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) अपलोड करने वाली ग्राम पंचायतों के संदर्भ में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में कुल कितने प्रतिशत ग्राम पंचायतें वर्तमान में ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हैं, इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) शेष पंचायतों के बीच अपनाने की दर बढ़ानेके लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या पंचायतों के कामकाज को और मजबूत करने और शासन में सुधार के लिए ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के लिए भविष्य में किसी संवर्द्धन या अतिरिक्त सुविधाओं की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ) जी हाँ। पंचायती राज मंत्रालय, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य -शासन और सेवा प्रदयगी में उनकी दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाकर पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना, मैन्युअल त्रुटियों को कम करने के लिए नियोजन, बजट, लेखांकन, निगरानी और सामाजिक लेखापरीक्षा जैसे पंचायत कार्यों को स्वचालित करना, ग्रामीण नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करना और पंचायत अधिकारियों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल उपकरण प्रदान करनाहै।

विगत उपलब्धियों के आधार पर, ई-एमएमपी परियोजना के तहत, 24 अप्रैल 2020 को मंत्रालय द्वारा

पंचायती राज संस्थाओं के लिए उद्यम संसाधन नियोजन (ई.आर.पी.) समाधान ई-ग्रामस्वराज लॉन्च कियागया था। यह एप्लिकेशन पंचायत के कामकाज के सभी पहलुओं जैसे नियोजन, बजट, लेखांकन, निगरानी, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि को ऑनलाइन भुगतान सहित एकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर शामिल करता है। अब तक,2.54 लाख ग्राम पंचायतों ने 2024-25 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) तैयार और अपलोड कीजा चुकी हैं। इसके अलावा, 2.41 लाख ग्राम पंचायतों ने 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के लिए ऑनलाइन लेनदेन पूरा कर लिया है। ईग्रामस्वराज को राज्यवार अपनाने की जानकारी **अनुबंध -I**में दी गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय नेजमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत ऑडिटऑनलाइन नामक एप्लीकेशन शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड करता है। ऑडिट वर्ष 2022-23 के लिए,2.58 लाख ऑडिट प्लान तैयार किए गए हैं और 2.57 लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

मंत्रालय द्वारापंचायत प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए मेरी पंचायत और पंचायत निर्णय जैसे ऐप भी शुरू किए जा चुके हैं। जहां मेरी पंचायत योजना, गतिविधियों और कार्य प्रगति की जानकारी जनता के लिए सुलभ बनाती है, वहीं पंचायत निर्णय ग्राम सभा की कार्यवाही में पारदर्शिता और प्रबंधन को बढ़ाता है।

(ङ) पंचायती राज मंत्रालय ने ई-पंचायत एमएमपी के तहत डिजिटल समावेशिता और पहुँच की आसानी सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन जैसे उपयोगकर्ता-अनुकूल (यूजरफ्रेंडली) सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों का विकास, भाषिनी के साथ एकीकरण करके इन ऑनलाइन एप्लिकेशन के लिए बहुभाषी सहायता प्रदान करना और डिजिटल टूल का उपयोग करने पर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल है।

इसके अलावा, दूरदराज के इलाकों में पंचायतों को डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए, उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं के प्रस्ताव के आधार पर, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत, मंत्रालय कंप्यूटर की खरीद के लिए सीमित पैमाने पर सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा कर रहा है।

सभी राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, ई-पंचायत एमएमपी को लागू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में राज्यों द्वारा डिजिटल एप्लिकेशनको अपनाने में पर्याप्त सुधार हुआ है। साथ ही, पंचायतों द्वारा ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन को अपनाने की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।इसकेअलावा,केंद्रीय वित्त आयोग के तहत धनजारी करने के लिए पंचायतों द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर पंचायत विकास योजना तैयार करना और अपलोड करनाअनिवार्य शर्तों में से एक है।

(च) ई-एमएमपी परियोजना के परिणामों में सुधार और जमीनी स्तर पर बेहतर शासन के लिए, मंत्रालय नियमित रूप से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ रहा है और प्राप्त फीडबैक के आधार पर, निरंतर आधार पर ई-ग्रामस्वराज में आवश्यक सुधार और संवर्द्धन किए जा रहे हैं।

***

अनुबंध-I

'ई-ग्रामस्वराज के कार्यान्वियन' के संबंध में दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1244 के भाग ((क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनाना

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या एवं समतुल्य	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान के साथ ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान के साथ ब्लॉक पंचायतें		जिला पंचायतों की कुल संख्या	ऑनबोर्ड जिला पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान वाली जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13328	13296	12907	660	660	639		13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2106	185	0	0	0		25	25	7
3	असम	2662	2197	2170	191	191	185		30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8044	534	534	529		38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11596	11594	11503	146	146	146		27	27	27
6	गोवा	191	191	89	0	0	0		2	2	2
7	गुजरात	14656	14594	13666	248	248	248		33	33	33
8	हरियाणा	6225	6221	5829	143	143	131		22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	3509	81	81	80		12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4317	264	264	262		24	24	23
11	कर्नाटक	5954	5954	5935	238	232	117		31	31	28
12	केरल	941	941	940	152	152	152		14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23009	22973	313	313	310		52	52	52
14	महाराष्ट्र	27911	27834	26268	351	351	302		34	34	34
15	मणिपुर	3180	161	120	0	0	0		12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0		3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0		0	0	0
18	नागालैंड	1289	186	0	0	0	0		0	0	0

19	ओडिशा	6794	6794	6792	314	314	314		30	30	30
20	पंजाब	13237	13222	9173	152	151	110		22	22	19
21	राजस्थान	11211	11206	10739	361	353	351		33	33	33
22	सिक्किम	199	199	194	0	0	0		6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12518	388	388	388		36	36	36
24	तेलंगाना	12771	12768	12628	540	540	498		32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1176	1162	75	75	75		9	9	8
26	उत्तराखंड	7795	7794	7729	95	95	95		13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57596	826	826	821		75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3338	345	345	345		22	21	21
कुल		**263481**	**251853**	**241156**	**8658**	**6402**	**6098**		**650**	**642**	**609**

***